

18 दिसंबर, 2021 करेंट अफेयर्स

1. भारत-पोलैंड ने आपराधिक मामलों में सहायता के लिए एक संधि पर किये हस्ताक्षर:



हाल ही में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए भारत और पोलैंड संधि को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु:

- यह संधि मूल रूप से पारस्परिक कानूनी सहायता के माध्यम से अपराधों की जांच और अभियोजन में भारत के साथ-साथ पोलैंड की क्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से है। इसमें आतंकवाद से जुड़े अपराध भी शामिल होंगे।
- इसका उद्देश्य पारस्परिक कानूनी सहायता के माध्यम से अपराध की जांच और अभियोजन में प्रभावशीलता को बढ़ाना भी है।

- अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद से इसके संबंधों के संबंध में, यह संधि अपराध की जांच और अभियोजन में पोलैंड के साथ द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगी।
- यह आतंकवादी कृत्यों को वित्तपोषित करने के लिए निधियों सहित अपराध की आय और उपकरणों का पता लगाने, रोकथाम और इसकी जब्ती में द्विपक्षीय सहयोग प्रदान करेगा।
- यह संधि पोलैंड को शामिल करके आपराधिक गतिविधियों से निपटने में भारत की प्रभावशीलता को भी बढ़ाएगी।

भारत-पोलैंड के बीच संबंध:

- भारत और पोलैंड के बीच राजनयिक संबंध 1954 में स्थापित किए गए थे। इसके बाद, भारत ने 1957 में वारसॉ में अपना दूतावास खोला।
- उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद के विरोध के आधार पर दोनों देशों ने समान वैचारिक धारणाओं को साझा किया।
- 1944 और 1989 के दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंध घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण थे, जो देश के व्यापारिक संगठनों के बीच नियमित उच्च स्तरीय यात्राओं, नियोजित व्यापार और आर्थिक बातचीत द्वारा समर्थित थे।
- हाल के वर्षों में उनके बीच सौहार्दपूर्ण राजनीतिक संबंध उभरे हैं, विशेषकर 2004 में पोलैंड के यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद। और इसके परिणामस्वरूप, पोलैंड मध्य यूरोप में भारत का प्रमुख आर्थिक भागीदार बन गया।

आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:

पोलैंड, मध्य यूरोपीय क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और निर्यात गंतव्य है। और पिछले दस वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर सात गुना हो गया है। पोलैंड में भारतीय निवेश 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जबकि भारत में पोलिश निवेश 672 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

सांस्कृतिक संबंध:

पोलैंड में इंडोलॉजी अध्ययन की परंपरा है। पोलिश विद्वानों ने 19वीं शताब्दी में संस्कृत का पोलिश में अनुवाद किया था। 2019 में, पोलिश मिशन ने महात्मा गांधी की 150 वीं वर्षगांठ का आयोजन किया था। 21 जून, 2015 को पोलैंड के 21 शहरों में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी आयोजन किया गया।

2. आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक:



आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है।

सूचकांक में राज्यों की चार श्रेणियां:

इस सूचकांक ने राज्यों को चार श्रेणियों में विभाजित किया है:

1. बड़े राज्य
2. छोटे राज्य
3. उत्तर पूर्व
4. केंद्र शासित प्रदेश

कौन सा संगठन यह सूचकांक रिपोर्ट तैयार करता है?

'इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस' द्वारा 'फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी पर इंडेक्स' रिपोर्ट तैयार की गई है। इसे प्रधान मंत्री (ईएसी-पीएम) की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, बिबेक देबरॉय द्वारा जारी किया गया था।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में साक्षरता के संकेतक के रूप में कार्य करता है।
- 'बड़े राज्यों' की श्रेणी में बिहार सबसे नीचे रहा।
- 'छोटे राज्यों' की श्रेणी में केरल ने सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
- इस सूचकांक में झारखंड सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बनकर उभरा।
- बड़े राज्य श्रेणी में केरल ने 67.95 स्कोर किया जबकि पश्चिम बंगाल ने छोटे राज्य श्रेणी में 58.95 स्कोर किया।

- संघ राज्य क्षेत्र में, लक्षद्वीप 52.69 के स्कोर के साथ सूचकांक में सबसे ऊपर है।
- पूर्वोत्तर श्रेणी में मिजोरम, 51.64 के स्कोर के साथ सबसे ऊपर है।
- 50 प्रतिशत से अधिक राज्यों ने राष्ट्रीय औसत 28.05 से नीचे स्कोर किया।

सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले:

- केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में, लद्दाख सबसे नीचे सूचीबद्ध था।
- उत्तर पूर्व श्रेणी में, अरुणाचल प्रदेश अंतिम स्थान पर आया है।

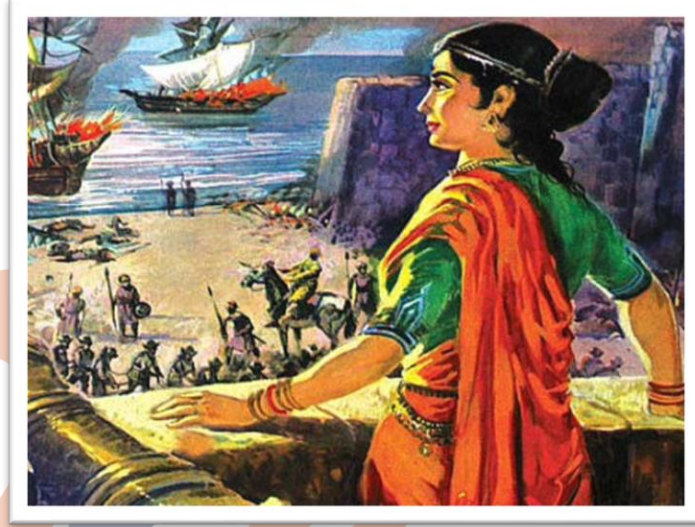
आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर सूचकांक:

'मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर सूचकांक' भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बीच मूलभूत शिक्षा की समग्र स्थिति की समझ स्थापित करता है। इसमें पांच स्तंभ हैं, जिसमें 41 संकेतक शामिल हैं। इन पांच स्तंभों में शामिल हैं:

1. शैक्षिक अवसंरचना
2. शिक्षा तक पहुंच
3. बुनियादी स्वास्थ्य
4. सीखने के परिणाम और
5. शासन

इन पांच स्तंभों में से, राज्यों ने विशेष रूप से शासन स्तंभ में खराब प्रदर्शन किया है।

3. खबरों में वीरा रानी अब्बक्का:



उल्लाल वीरा रानी अब्बक्का उत्सव समिति ने हाल ही में दिसंबर 2021 में वीरा रानी अब्बक्का उत्सव के दौरान "वीरा रानी अब्बक्का पुरस्कार" प्रदान करने का निर्णय लिया।

प्रमुख बिंदु:

- यह पुरस्कार 21 दिसंबर, 2021 को एक उपलब्धि प्राप्त करने वाली महिला को प्रदान किया जाएगा।
- इसमें एक पुरस्कार और पुरस्कार में नकद और पुरस्कार पैनल शामिल हैं।
- 21 दिसंबर को वीरा रानी अब्बक्का उत्सव की रजत जयंती भी है।

- उल्लाल नगर पालिका परिसर में 21 दिसंबर को उत्सव मनाया जाएगा।

किसे सम्मानित किया जाएगा?

- वीरा रानी अब्बक्का पुरस्कार, उस महिला को दिया जाएगा जिसने अनुसंधान और संस्कृति में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है।
- समिति, पुरस्कार प्रदान करने के लिए मातृभाषा और परंपरा को भी ध्यान में रखेगी।
- तुलु पृष्ठभूमि वाली महिला को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिसने खेल, कला, समाज सेवा और ऐसे अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त उपलब्धि प्राप्त की है।

रानी अब्बक्का चौटा:

- रानी अब्बाका चौटा, उल्लाल की पहली तुलुवा रानी थीं। उन्होंने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ी।
- रानी, चौटा वंश की थीं, जिन्होंने तटीय कर्नाटक (तुलु नाडु) के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। राजवंश की राजधानी पुट्टीगे थी। उल्लाल का बंदरगाह शहर उनकी सहायक राजधानी थी। उल्लाल को रणनीतिक रूप से रखा गया था, जिसके कारण पुर्तगालियों ने इसे पकड़ने के कई प्रयास किए।
- लेकिन रानी ने चार दशकों से अधिक समय तक उनके हमलों को का कड़ा जवाब दिया। उनकी बहादुरी के कारण उन्हें अभय रानी के नाम से जाना जाने लगा।

4. "तमिल थाई वज़्थु" तमिलनाडु का राज्य गीत घोषित:



हाल ही में, तमिलनाडु सरकार ने "तमिल थाई वज़्थु" को राज्य गीत के रूप में घोषित किया।

मुख्य तथ्य:

- "तमिल थाई वज़्थु" एक प्रार्थना गीत है, जो तमिल माँ की स्तुति में गाया जाता है।
- यह 55 सेकंड का गीत है और राष्ट्रगान के आधार पर सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और इसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में समारोह की शुरुआत में गाया जाता है।

एचसी में कान इलांगो बनाम राज्य का मामला:

- तमिल थाई वज़्थु गीत पर न्यायमूर्ति जी. आर स्वामीनाथन ने कान इलांगो बनाम राज्य मामले में 6 दिसंबर को टिप्पणी की थी।

- राज्य का प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक और अन्य ने किया। उच्च न्यायालय ने कान इलांगो के नेतृत्व वाले व्यक्तियों के एक समूह के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया।
- इस समूह ने कथित तौर पर 2018 में रामेश्वरम में कांची मठ शाखा में प्रवेश किया और नारेबाजी की।
- उन्होंने कांची मठ के प्रबंधक को भी आपराधिक रूप से धमकाया।

मामला क्या था?

उस समूह के प्रदर्शनकारी नाम तमिलर काची के थे, जो सेंथमिज़न सीमन के नेतृत्व वाला एक तमिल राष्ट्रवादी संगठन है। वे कांची कामकोटि पीठम के पुजारी के विरुद्ध, विरोध कर रहे थे, जो एक समारोह के दौरान बैठे थे, जबकि तमिल थाई वाजथु बजाया जा रहा था। इससे काफी आक्रोश फैल गया था।

तमिल थाई वजुथु पर कोर्ट का रुख:

न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तमिल थाई वजुथु एक प्रार्थना गीत है न कि एक गान। प्रार्थना गीत को सबसे अधिक श्रद्धा और सम्मान दिया जाना चाहिए लेकिन इसके लिए खड़े होना आवश्यक नहीं है।

न्यायालय के रुख का तर्क:

कोर्ट ने 17 जून, 1970 को तमिलनाडु सरकार के एक आह्वान का संदर्भ दिया। तब, सरकार ने निर्देश दिया था कि सरकार, स्थानीय निकायों, शिक्षण संस्थानों और उनके द्वारा आयोजित सभी

कार्यक्रमों की शुरुआत में 'मनोनमनेयम' के एक गीत को प्रार्थना गीत के रूप में गाया जाना चाहिए। मनोनमनेयम, पी. सुंदरम पिल्लई द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध तमिल नाटक है।

5. WHO ने Covovax के टीके के लिए आपातकालीन सहमति दी:



हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी।

मुख्य तथ्य:

- WHO, ने आपातकालीन उपयोग के लिए Covovax को नौवें COVID-19 वैक्सीन के रूप में सूचीबद्ध किया है। इस कदम का उद्देश्य कम आय वाले देशों में टीकाकरण की पहुंच बढ़ाना है।
- सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई), नोवावैक्स के लाइसेंस के अंतर्गत कोवोवैक्स का उत्पादन करता है।

पृष्ठभूमि:

हाल ही में, SII के सीईओ, अदार पूनावाला ने घोषणा की कि SII ने अगले छः महीनों में बच्चों के लिए Covovax नामक एक COVID-19 वैक्सीन लॉन्च करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि इस टीके का परीक्षण चल रहा है और यह तीन वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करेगा।

डब्ल्यूएचओ की सहमति:

डब्ल्यूएचओ ने कोवोवैक्स को उसकी आपातकालीन उपयोग सूची (ईयूएल) प्रक्रिया के अंतर्गत गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता पर डेटा की समीक्षा, एक प्रोग्रामेटिक उपयुक्तता, जोखिम प्रबंधन योजना, और निर्माण स्थल निरीक्षण के आधार पर मूल्यांकन के बाद सहमति दे दी, जो कि भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल द्वारा किया जाता है।

नोवावैक्स COVID-19 वैक्सीन:

Novavax COVID-19 वैक्सीन को Nuvaxovid और Covovax ब्रांड नाम से बेचा जाता है। इस सबयूनिट COVID-19 वैक्सीन को

Novavax और Coalition for Epidemic Preparedness

Innovations (CEPI) द्वारा विकसित किया गया है। Covovax ब्रांड नाम के अंतर्गत भारत में वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। यह 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है।

कोवोवैक्स की खुराक:

वैक्सीन को 21 दिनों के अंतराल पर दो खुराक में दिया जाता है।

सबयूनिट वैक्सीन:

सबयूनिट वैक्सीन में रोगजनक के शुद्ध हिस्से शामिल होते हैं जो एंटीजेनिक होते हैं, या एक सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें संपूर्ण रोगजनक शामिल नहीं है, जैसा कि जीवित क्षीण या निष्क्रिय टीके में उपस्थित होता है। लेकिन इसमें केवल प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड या पेप्टाइड जैसे एंटीजेनिक भाग होते हैं।

वैक्सीन की स्थिरता:

चूंकि सबयूनिट टीके में रोगजनक के जीवित घटक नहीं होते हैं, इसलिए रोग के शुरू होने का कोई जोखिम नहीं होता है। यह पूरे रोगजनकों वाले टीके की तुलना में अधिक सुरक्षित और अधिक स्थिर होता है।

6. बिहार में देखा गया खलिहान उल्लू:



हाल ही में, वन अधिकारियों ने बिहार के सुपौल जिले में एक खलिहान उल्लू को बचाया।

मुख्य तथ्य:

- खलिहान उल्लू आमतौर पर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के अन्य हिस्सों का मूल निवासी है।
- यह भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत कम देखा जाता है।

खलिहान उल्लू:

- खलिहान उल्लू को वैज्ञानिक रूप से टाइटो अल्बा कहा जाता है।
- यह दुनिया भर में उल्लू की सबसे व्यापक रूप से वितरित प्रजाति है।
- यह प्रजाति हिमालय के उत्तर में ध्रुवीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों, इंडोनेशिया, प्रशांत द्वीप समूह और एशिया को छोड़कर, दुनिया भर में लगभग हर जगह पाई जाती है। इसे आम खलिहान उल्लू भी कहा जाता है।

इस उल्लू की विशेषताएं:

- खलिहान उल्लू अपनी अधिकांश सीमा के लिए निशाचर है। हालाँकि, ग्रेट ब्रिटेन और कुछ प्रशांत द्वीपों में, उल्लू दिन में भी शिकार करता है।
- वे जमीन पर जानवरों का शिकार करने में माहिर हैं। उनके सभी भोजन में छोटे स्तनधारी होते हैं, जिन्हें वे ध्वनि द्वारा खोजते हैं।
- वे मध्यम आकार के, हल्के रंग के उल्लू होते हैं, जिनके लंबे पंख और एक छोटी और चौकोर पूंछ होती है।
- उनके पास 80 से 95 सेमी का एक विशिष्ट पंख होता है।

प्रजनन का मौसम:

उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, खलिहान उल्लू वर्ष के किसी भी समय प्रजनन कर सकते हैं। हालांकि, घोंसले के शिकार में कुछ मौसमी चीजें अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अलग-अलग गीले और सूखे मौसम के क्षेत्रों में, अंडे देना आमतौर पर शुष्क मौसम के दौरान होता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे शुष्क क्षेत्रों में, प्रजनन अनियमित हो सकता है और नम अवधि में हो सकता है।

7. गेब्रियल बोरिक होंगे चिली के अगले राष्ट्रपति:



19 दिसंबर, 2021 को, एक वामपंथी, सहस्राब्दी गेब्रियल बोरिक को चिली के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया।

मुख्य तथ्य:

- पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की तुलना में एक फ्री-मार्केट फायरब्रांड के विरुद्ध अभियान के बाद, उन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था।
- गेब्रियल 56 प्रतिशत मतों से जीते।

गेब्रियल बोरिक फ़ॉन्ट:

गेब्रियल बोरिक फ़ॉन्ट चिली के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। वह मार्च 2014 से चैंबर ऑफ़ डेप्युटी के सदस्य थे, और मैगलन और अंटार्कटिक जिले का प्रतिनिधित्व करते थे। 2013 के आम चुनाव में, उन्हें एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। 2017 में उन्हें फिर से चुना गया। दोनों चुनावों में, उन्हें मैगलन क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों के बीच सबसे अधिक वोट मिले। 2021 के आम चुनाव के लिए, उन्होंने 60% लोकप्रिय वोट के साथ, अप्रुएबो डिग्रीडाड प्रेसिडेंशियल प्राइमरी जीता। इस प्रकार, वह वामपंथी चुनावी गठबंधन के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए। वह साल्वाडोर अलेंदे के बाद चिली के पहले समाजवादी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

चिली- प्रमुख तथ्य

चिली को आधिकारिक तौर पर चिली गणराज्य कहा जाता है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में एक देश है। देश एंडीज और प्रशांत महासागर के बीच भूमि की एक लंबी, संकरी पट्टी तक फैला है।

यह विश्व का सबसे दक्षिणी देश है। यह अंटार्कटिका के सबसे करीब है, और पेरू, बोलीविया, अर्जेन्टीना और ड्रेक पैसेज के साथ सीमा साझा करता है।

8. चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021:



आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में 'चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021' पेश किया।

बिल के बारे में:

चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021, चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को एक बार पारित होने के बाद मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के इच्छुक लोगों की आधार संख्या पूछने की अनुमति देगा। वे पहचान स्थापित करने के लिए आधार नंबर मांगेंगे।

इस विधेयक में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को उन व्यक्तियों से आधार संख्या मांगने की अनुमति देने का भी प्रयास किया गया है जो पहले से ही मतदाता सूची में शामिल हैं। यह मतदाता सूची में प्रविष्टियों को प्रमाणित करने के साथ-साथ एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति के नाम के पंजीकरण की पहचान करने या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में

एक से अधिक बार नाम के पंजीकरण की पहचान करने के लिए किया जाएगा।

यह विधेयक यह भी स्पष्ट करता है कि, "मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए किसी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा और मतदाता सूची में व्यक्तियों की अक्षमता के लिए कोई प्रविष्टि नहीं हटाई जाएगी, इस तरह के पर्याप्त कारण की वजह से आधार संख्या को सूचित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

ऐसे लोगों को अन्य वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

किन अधिनियमों में होगा संशोधन?

- यह बिल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 की कई धाराओं में संशोधन करेगा।
- मतदाता सूची डेटा को, आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने की अनुमति देने के लिए अधिनियम 1950 की धारा 23 में संशोधन किया जाएगा। यह संशोधन विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति के एकाधिक नामांकन के खतरे को रोकने में सहायता करेगा।
- 1950 अधिनियम की धारा 14 में संशोधन किया जाएगा ताकि मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र लोगों के लिए चार "अर्हतापूर्ण" तिथियां हों।
- 1950 अधिनियम की धारा 20 और 1951 की धारा 60, सेवा मतदाताओं के लिए चुनाव को लिंग तटस्थ बनाने की अनुमति

देगा। यह संशोधन "पत्नी" शब्द को "पति / पत्नी" शब्द से बदल देगा।

- वर्तमान चुनावी कानून के अनुसार, सेना के एक जवान की पत्नी सेवा मतदाता के रूप में नामांकित होने की हकदार थी, लेकिन एक महिला सेना अधिकारी का पति नहीं था। इस प्रावधान में परिवर्तन किया जाएगा क्योंकि पत्नी शब्द को जीवनसाथी शब्द से बदल दिया जाएगा।